दिनांक : 03 मार्च 2014

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा

– अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

देश के पूर्वी भाग में ऐसे बहुत से राज्य हैं, जिन्होंने अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से प्रगति नहीं की है। इन राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण इन्हें परेशानी उठानी पड़ी है। उनका संसाधन जुटाने का काम भी अपर्याप्त है। यही कारण है कि ये राज्य विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं ताकि उनहें अधिक केन्द्रीय राजस्व और अनुदान मिल सके।

बिहार एक ऐसा राज्य है जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। मूल बिहार का बिहार और झारखंड के बीच बंटवारा होने के कारण प्राकृतिक संसाधन झारखंड के पास चले गए। बिहार में इन वर्षों में एनडीए सरकार ने कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। बिहार के राजनैतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर लगभग आम सहमति बन चुकी थी। कांग्रेस की पिछले दो वर्षों में जद (यू) पर कृपा बरसने लगी और उसने कह दिया कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर विचार करने को तैयार है। 2013 के आम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार बिहार को विशेष राजय का दर्जा देने के बारे में विचार करने के लिए एक समिति गठित करेगी। यह आश्वासन बिहार की आर्थिक जरुरतों की तुलना में राजनीतिक ज्यादा था। यूपीए का इरादा जद (यू) को सब्जबाग दिखाना था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने ही वाला है। मैं नहीं जानता कि जद(यू) का बुद्धिमान नेतृत्व उसके बहकावे में कितना आया होगा। संयोग की बात है कि विशेष राज्य का दर्जा देने का संकेत उसी समय दिया गया जब जद (यू)–भाजपा के संबंधों में कड़वाहट आ चुकी थी। जब जद (यू) अलग हो गई तब विशेष दर्जे की बात नहीं आई। साथ ही आरजेडी और जद (यू) के बीच स्वयंवर में कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने सहयोगी के साथ ही जाना उचित समझा। हांलाकि अखबारों में प्रकाशित खबरों में संकेत दिया गया हे आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे में गतिरोध पैदा हो गया है। जद (यू) ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन आयोजित किया। मीडिया ने यह भी संकेत दिया है कि जद (यू) कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम करने की भी कोशिश कर सकती है, जो पार्टी विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर पहले ही धोखा दे चुकी है।

*****